THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES (SHRI BRAJAMOHAN MOHANTY) (a) to (c). It is presumed that the Question relates to the Super Bazar, Delhi which is under the administrative control of this Ministry. The Vice-President of the Super Bazar, Delhi is not enjoying any privileges and perks over and above the normal entitlement.

विदेशी मुद्रा रिजर्व में वृद्धि करने के उपाय

750. **श्री विलास मुत्तेमवार :**
श्रीमती कृष्णा साही :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में कमी आने से संबंधित समाचारपत्रों मे प्रकाशित समाचारों में क्या सच्चाई है ;

(ख) सही स्थिति दर्शाने वाले वास्तविक आंकडे क्या है , और

(ग) विदेशी मुद्रा रिजर्व बैंक में कमी के क्या कारण हैं तथा उसमें वृद्धि करने के लिए क्या प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री भगत भाई बारोट) :

(क) और (ख) : मार्च 1980 के अन्त में सोने और एस० डी० आर० को छोड़ कर भारत का विदेशी मुद्रा भडार 5163.66 करोड़ रुपये का था जो 7 नवम्बर, 1980 को 4965.72 करोड़ रुपये का रह गया, अर्थात् इस में 197.94 करोड़ रुपये की कमी हो गई । यह राशि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की न्यास निधि (ट्रस्ट फंड) और प्रतिपूरक वित्तपोषण सुविधा (कम्पेन्सेटरी फाइनेंसिंग फेसिलिटि) से की जाने वाली कुल मिला कर लगभग 815 करोड़ रुपये की निकासियों को हिसाब में लेने के बाद आंकी गई है ।

(ग) विदेशी मुद्रा भंडार में होने वाले परिवर्तन अन्य देशों के साथ भारत के लेनदेनों का निवल परिणाम होते हैं, जिनका ब्यौरा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा शोधन शेष के आंकड़ों का संचलन कर लिए जाने के बाद ही उपलब्ध होगा । किन्तु स्थूल संकेतों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार (सोने और एस० डी० आर० को छोड़ कर) में कमी मुख्य रूप से बहुत बड़े व्यापारिक घाटे के कारण हुई है । यह घाटा एक ओर मध्यवर्ती वस्तुओं और कच्चे माल, खाद्य तेलों जैसी आम उपयोगी की वस्तुओं के अधिक आयात, कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों, उर्वरकों, लौह और अलौह धातुओं आदि की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतो मे वृद्धि के परिणामस्वरूप आयात बिल के काफी बढ़ जाने और दूसरी निर्यातों के विकास की अपेक्षाकृत धीमी गति होने के कारण हुआ है ।

सरकार विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव को कम करने और उसके भावी विकास के मार्ग मे आने वाली रूकावटो को दूर करने के लिए कई उपाय करनी रही है जिनमे ये शामिल है .

1. कोयला, बिजली, रेल, पत्तन जैसे मुख्य क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन और सामान्य मूलभूत ढांचे में सुधार के उपाय करना ताकि औद्योगिक क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित हो सके और आन्तरिक उत्पादन में सुधार करना तथा आयात की आवश्यकताओं को भी यथासंभव कम करना ।

2. निर्यात की क्षमता वाली मदों के उत्पादन पर जोर देने जैसे निर्यात को

बढ़ाने के प्रयत्न करना ताकि निर्यात के लिए बड़ी मात्रा में माल उपलब्ध हो सके ; निर्धारित मूल्य (वेल्यू एडिड) की मदों और खासतौर से निर्मित और अर्धनिर्मित वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन देना ; नौवहन की और पत्तनों पर भीड़ भाड़ की समस्याओं को हल करना और विदेशों में विपणन संबंधी आसूचना का समन्वय करना और उसे सुदृढ़ बनाना ।

3. चालू राजकोषीय वर्ष 1980–81 के लिए आयात नीति में निर्यात को प्रधानता दी गई है ।

4. देश में भेजी जाने वाली राशियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अन्य योजनाओं के साथ साथ निम्नलिखित योजनाएं शुरू की है :—

(i) अनिवासी (बाह्य) खाता योजना, जिसके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को रुपए में विनिर्दिष्ट खाते खोलने की अनुमति दी गई है । ऐसे खातों की शेष राशि मुक्त रूप से प्रत्यावर्तित की जा सकती है और जमा राशि पर होने वाली आय भारतीय आयकर से मुक्त होती है ।

(ii) विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता योजना जिसके अन्तर्गत विदेशों में रहने वाले भारतीयों को विनिर्दिष्ट करेंसियों (पौंड, स्टर्लिंग अथवा अमेरिकी डालर) में खाते खोलने की अनुमति दी गई है और मूलधन और उन पर मिलने वाला ब्याज, जो आयकर से मुक्त होता है, उसी करेंसी में प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ।

(iii) कतिपय औद्योगिक उपक्रमों में निवेश की अनुमति की योजना जिसके अन्तर्गत निवेश की गई 74 प्रतिशत राशि प्रत्यावर्तित की जा सकती है ।

(iv) नई भारतीय कंपनियों के नए इक्विटी शेयरों में 20 प्रतिशत तक पूंजी निवेश की अनुमति की योजना जिसे प्रत्यावर्तित किया जा सकता है ; और

(v) स्वदेश लौटने वाले भारतीयों के लिए विदेशी मुद्रा का हकदारी योजना (रिटर्निंग इंडियन्स फारेन एन्टाइटलमेंट स्कीम) जिसके अन्तर्गत अनिवासी भारतीयों को पहली नवम्बर, 1977 को अथवा उसके बाद भारत में अपने निवास का स्थानान्तरण करने पर, 10 वर्ष की अवधि तक देश में भेजी गई अथवा सामान्य बैंकों के माध्यम से लाई गई विदेशी मुद्रा के 25 प्रतिशत तक राशि विदेश यात्रा, डाक्टरी इलाज, विदेशों में बच्चों की शिक्षा, निकट संबंधियों को उपहार, व्यावसायिक उपयोग के लिए विशेष उपकरणों के आयात जैसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है, बशर्ते कि आयात लाइसेंस संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई हों, देश में भेजी जाने वाली राशियों के संबंध में सुविधाओं और प्रक्रियाओं आदि की बराबर समीक्षा की जाती है ताकि देश में भेजी जाने वाली राशियों को प्रोत्साहन दिया जा सके और विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि की जा सके ।

Shortage of essential Commodities

751. SHRI CHITTA MAHATA: Will the Minister of CIVIL SUPPLIES be pleased to state the extent of shortage of essential commodities in the